नईदुनिया

संक्षिप्त समाचार

चावल, चीनी, दालों में तेजी; गेहूं नरम; खाद्य तेलों में उतार-चढ़ाव

नयी दिल्ली। घरेलू थोक जिंस बाजारों में बुधवार को चावल की औसत कीमत बढ़ गयी। चावल के साथ दालों और चीनी में भी तेजी रही। वहीं, गेहूं में गिरावट देखी गयी। खाद्य तेलों में उतार-चढ़ाव का रुख रहा। औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत तीन रुपये बढ़कर 3,850 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गयी। गेहूं 16 रुपये सस्ता हुआ और 2,798 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। आटे के भाव में टिकाव रहा। दाल-दलहनों में तेजी रही। तुअर दाल की औसत कीमत 52 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गयी। मूंग दाल 20 रुपये और उड़द दाल 18 रुपये महंगी हुई। चना दाल का भाव नौ रुपये और मसूर दाल का सात रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा। विदेशों में मलेशिया के बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में पाम ऑयल का मई वायदा 71 रिंगिट की मजबूती के साथ 4,499 रिंगिट प्रति टन पर पहुंच गया। मई का अमेरिकी सोया तेल वायदा 2.61 प्रतिशत की बढ़त में 67.33 सेंट प्रति पौंड बोला गया। स्थानीय बाजारों में मूंगफली तेल औसतन 139 रुपये प्रति क्विंटल महंगा हुआ। सूरजमुखी तेल की कीमत 96 रुपये और पाम ऑयल की 87 रुपये बढ़ी। वनस्पति में 57 रुपये की तेजी रही। सोया तेल की कीमत चार रुपये और सरसों तेल की तीन रुपये प्रति क्विंटल घट गयी। मीठे के बाजार में आज गुड़ का औसत भाव 29 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गया। चीनी भी 10 रुपये महंगी हुई।

सेल ने पहले 11 महीने की बिक्री का बनाया नया रिकॉर्ड

नयी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक और महारत्न कंपनी भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) ने चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीने में बिक्री का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कंपनी की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल-फरवरी के दौरान उसने 1.82 करोड़ टन इस्पात की बिक्री की जो किसी भी वित्त वर्ष के पहले 11 महीने में सबसे अधिक है। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि से 14 प्रतिशत ज्यादा है। इस दौरान उसका नकद संग्रह 1.11 लाख करोड़ रहा जो एक नया कीर्तिमान और सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की वृद्धि है। इस दौरान खुदरा बिक्री, स्टॉकयार्ड बिक्री और घर तक डिलीवरी में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। सेल ने फरवरी महीने में 15.8 लाख टन इस्पात की बिक्री की। इस साल जनवरी के मुकाबले फरवरी में इन्वेंट्री में 1.05 लाख टन की कमी दर्ज की गयी। अच्छे नकद संग्रह के दम पर कंपनी ने अपना कर्ज एक हजार करोड़ रुपये कम करने में सफलता पायी है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बाजार की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सेल ने चेकर्ड प्लेट्स का उत्पादन फिर से शुरू कर दिया है। कंपनी ने झारखंड के बोकारो स्थित संयंत्र में पहली बार चेकर्ड प्लेट्स का उत्पादन शुरू किया है। सेल के निदेशक (वित्त) ए.के. पांडा ने इस प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा, हम बाजार के अनुरूप ढलने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इन्वेंट्री और वर्किंग कैपिटल का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करके हम उस वित्तीय अनुशासन का प्रदर्शन कर रहे हैं जो कंपनी की नींव को मजबूत करता है। इसके साथ ही, हमारी रिकॉर्ड बिक्री और नकद संग्रह हमारे ग्राहकों द्वारा हम पर जताये गये भरोसे का प्रमाण है।

एआईएफ के डिस्क्लोजर नियमों में बदलाव के संकेत, सेबी कर सकता है नए सुधार

मुंबई। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (एआईएफ) से जुड़े डिस्क्लोजर नियमों में बदलाव कर सकता है। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने बुधवार को एक कार्यक्रम में इसके संकेत दिए। इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेटिव कैपिटल एसोसिएशन (आईवीसीए) के एक कार्यक्रम में बोलते हुए पांडेय ने कहा कि एआईएफ मुख्य रूप से अनुभवी निवेशकों के लिए बनाए गए निवेश साधन हैं। इनमें अक्सर गैर-तरल परिसंपत्तियां, जटिल संरचनाएं और लंबी निवेश अवधि शामिल होती है, इसलिए निवेशकों को इनके जोखिमों और संरचना को अच्छी तरह समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि फंड प्रबंधकों और वितरकों को केवल औपचारिक जोखिम खुलासे तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निवेशक जिस उत्पाद में निवेश कर रहे हैं, उसे सही तरीके से समझें। पांडेय के अनुसार एआईएफ अब वित्तीय प्रणाली के हाशिये से निकलकर पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। ये फंड नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, आपूर्ति श्रृंखला और रणनीतिक विनिर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं, जहां पारंपरिक ऋणदाताओं की पहुंच सीमित होती है। उन्होंने संकेत दिया कि सेबी एआईएफ के लिए संतुलित नियामकीय दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें सख्त निगरानी के साथ आवश्यक लचीलापन भी शामिल होगा। एआईएफ इकाइयों और निवेशों के विमुद्रीकरण तथा डिपॉजिटरी को शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) की रिपोर्टिंग जैसे कदम पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने के लिए उठाए गए हैं। सेबी केवल मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए बनाई गई योजनाओं को अधिक लचीले नियामकीय ढांचे में संचालित करने पर भी विचार कर रहा है। इसके अलावा नई एआईएफ योजनाओं के लॉन्च को तेज करने के लिए लाइटर लॉन्च मॉडल जैसे विकल्पों का अध्ययन किया जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार भारत में मान्यता प्राप्त निवेशकों की संख्या मई 2025 में 649 से बढ़कर फरवरी 2026 तक 2,100 से अधिक हो गई है, जो इस क्षेत्र में बढ़ती दिलचस्पी को दर्शाता है।

आईईए के रिजर्व जारी करने की खबरों से कच्चे तेल की कीमत 90 डॉलर के नीचे

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बुधवार को कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई और यह 90 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया। इसकी प्रमुख वजह इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) द्वारा इमरजेंसी रिजर्व से तेल जारी कर आपूर्ति बढ़ाने की संभावना बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद बढ़ी हुई तेल कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आईईए इमरजेंसी भंडार से कच्चे तेल की आपूर्ति जारी करने पर विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि प्रस्तावित आपूर्ति 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद जारी किए गए 182 मिलियन बैरल से भी अधिक हो सकती है। जी-7 देशों ने भी आईईए से ऐसे कदम के लिए तैयार रहने का आग्रह किया है। इन खबरों के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत करीब 0.99 प्रतिशत गिरकर 86.93 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) वायदा 0.75 प्रतिशत गिरकर 82.82 डॉलर प्रति बैरल रह गया।

वैकल्पिक आयात और घरेलू उत्पादन बढ़ाकर एलपीजी-एलएनजी उपलब्धता मजबूत

मध्य-पूर्व तनाव के बीच भारत ने बढ़ाई गैस आपूर्ति की तैयारी

नई दिल्ली। मध्य पूर्व में तनाव के चलते देश में एलपीजी की कमी की रिपोर्ट्स के बीच, भारत ने वैकल्पिक मार्गों से एलपीजी और एलएनजी की आपूर्ति हासिल कर ली है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, वैकल्पिक स्थानों से एलपीजी और एलएनजी की ये आपूर्ति जल्द ही देश में पहुंचने की संभावना है।

सरकार द्वारा तेल कंपनियों को कुकिंग गैस का उत्पादन अधिकतम करने का निर्देश दिए जाने के बाद से भारतीय रिफाइनरियों ने एलपीजी का घरेलू उत्पादन 10 प्रतिशत बढ़ा दिया है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जामनगर ऑयल रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स कुकिंग गैस एलपीजी के उत्पादन को अधिकतम स्तर पर ले जा रहा है। कंपनी ने एक बयान में कहा, वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता के इस दौर में, भारतीय घरों के लिए आवश्यक ईंधनों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता बनी हुई है। साथ ही, राष्ट्रीय ऊर्जा प्राथमिकताओं और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, केजी-डी6 बेसिन से उत्पादित प्राकृतिक गैस को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को आपूर्ति में सहयोग देने के लिए डायवर्ट किया जाएगा।

कंपनी ने कहा, रिलायंस

इंडस्ट्रीज सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप, जामनगर स्थित अपने रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स से एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। जामनगर दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत रिफाइनिंग हब है। हमारी टीमें रिफाइनरी संचालन को अनुकूलित करने और एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही हैं ताकि घरेलू बाजार में आपूर्ति स्थिर और विश्वसनीय बनी रहे।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पश्चिम एशिया से बाहर आयात स्रोतों में विविधता लाकर भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, जबकि क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। उन्होंने नागरिकों को आश्वस्त किया कि घरेलू गैस आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। पुरी ने कहा कि भारत विभिन्न स्रोतों और आपूर्ति मार्गों से ऊर्जा आयात प्राप्त करना जारी रखे हुए है, जिससे क्षेत्र में चल रहे संघर्ष के बावजूद देश में ईंधन की उपलब्धता में स्थिरता सुनिश्चित हो रही है।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने घरों और प्रमुख क्षेत्रों के लिए ईंधन आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। पुरी के अनुसार, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को सीएनजी और पीएनजी की पूरी आपूर्ति मिलती रहे।

संघर्ष से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद उद्योगों को उनकी गैस आवश्यकताओं का लगभग 70-80 प्रतिशत प्राप्त हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार देश भर के घरों को सस्ती ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मध्य-पूर्व तनाव से सोना-चांदी में उतार-चढ़ाव

मुंबई। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनावों के चलते वैश्विक बाजार में अस्थिरता के बीच बुधवार को कीमती धातुओं (सोने-चांदी) की कीमतों में बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला।

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के आंकड़ों के मुताबिक, बुधवार को 999 प्यूरिटी वाला गोल्ड 1,60,230 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंच गया, जबकि इससे पहले मंगलवार को 999 प्यूरिटी वाले गोल्ड की कीमत 1,60,188 रुपए थी। यानी एक दिन में सोने का भाव 42 रुपए महंगा हुआ है।

वहीं यदि चांदी की बात करें तो आईबीजेए के अनुसार, बुधवार को 999 प्यूरिटी वाली चांदी का भाव 2,66,010 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। इससे पहले बीते मंगलवार को इसकी कीमत 2,70,944 रुपए प्रति किलोग्राम थी। यानी आज चांदी के दाम में 4,934 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है।

वहीं अगर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने-चांदी की कीमतों की बात करें तो, खबर लिखे जाने तक (शाम करीब 5.57 बजे) अप्रैल डिलीवरी वाला सोना 955 रुपए यानी 0.58 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,62,348 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता नजर आया। वहीं मई डिलीवरी वाली चांदी

2.71 प्रतिशत यानी 7,524 रुपए गिरकर 2,70,326 पर पहुंच गई।

बाजार में सोने और चांदी में गिरावट पर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में कमोडिटीज एनालिस्ट मानव मोदी ने कहा कि युद्ध को लेकर मिले-जुले संकेतों के चलते माहौल अस्थिर बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले संकेत दिया था कि संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है, जबकि बुधवार की सुबह तक अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष से तत्काल तनाव कम होने के कोई संकेत नहीं मिले, जिससे युद्ध लगातार बारहवें दिन भी जारी रहा।

हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल से ईरान पर हमले रोकने का आग्रह किया, जबकि ईरान ने जहाजों के आवागमन को रोकने के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य में बारूदी सुरंगें बिछाने का दावा किया।

ऐसे में, अब कमोडिटी बाजार का ध्यान आगामी अमेरिकी उपभोक्ता मुद्रास्फीति आंकड़ों पर है, जो फेडरल रिजर्व के नीतिगत दृष्टिकोण के बारे में और संकेत दे सकते हैं, हालांकि ये आंकड़े संघर्ष से जुड़ी बढ़ती ऊर्जा कीमतों के मुद्रास्फीति प्रभावों को पूरी तरह से नहीं दर्शाएंगे।

एक्सपर्ट ने आगे बताया कि इस सप्ताह जारी होने वाले अमेरिकी जीडीपी और महंगाई के आंकड़े भी फोकस में रहेंगे, जिनसे आर्थिक स्थिति और आगे की मौद्रिक नीति के मार्ग के बारे में बेहतर स्पष्टता मिलेगी। इससे ही सोने और चांदी की आगे की चाल तय होगी।

सेंसेक्स करीब 1,000 अंक टूटा, बैंकिंग शेयरों में बिकवाली से बाजार में बड़ी गिरावट

मुंबई। भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को तेज गिरावट दर्ज की गई। दोपहर करीब 12 बजे बीएसई सेंसेक्स 987 अंक या 1.26 प्रतिशत गिरकर 77,218 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 275 अंक या 1.13 प्रतिशत कमजोर होकर 23,986 पर कारोबार करता दिखा। बाजार में गिरावट की अगुवाई बैंकिंग शेयरों ने की। निफ्टी बैंक करीब 1.6 प्रतिशत टूटकर 56,044 के स्तर पर आ गया। ऑटो, निजी बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, सर्विसेज, पीएसयू बैंक, एफएमसीजी, रियल्टी, डिफेंस, आईटी और इन्फ्रा सेक्टर के शेयरों में दबाव देखने को मिला। हालांकि फार्मा, एनर्जी, मीडिया, मेटल, हेल्थकेयर और ऑयल एंड गैस सेक्टर के कुछ शेयर हरे निशान में कारोबार करते नजर आए। विशेषज्ञों के अनुसार बाजार में गिरावट की मुख्य वजह विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली है। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को करीब 4,673 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने लगभग 6,333 करोड़ रुपये का निवेश किया।

भारत का मोबाइल फोन निर्यात बीते एक दशक में 127 गुना बढ़ा: वैष्णव

नई दिल्ली। भारत का मोबाइल फोन का निर्यात बीते एक दशक में 127 गुना से अधिक बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में दो लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो कि वित्त वर्ष 2014-15 में 0.01 लाख करोड़ रुपए था। यह जानकारी बुधवार को सरकार द्वारा संसद में दी गई।

लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोबाइल फोन के निर्यात में तेज बढ़ोतरी की वजह सरकार द्वारा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों की मदद से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना है। इन नीतियों का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के लिए एक संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम का निर्माण करना है। सरकार के अनुसार, भारत पिछले 11 वर्षों में मोबाइल फोन का शुद्ध आयातक होने से शुद्ध निर्यातक बन गया है।

उन्होंने कहा, देश अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। इसी अवधि के दौरान, भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का कुल उत्पादन लगभग छह गुना बढ़कर 2014-15 में लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए से 2024-25 में लगभग 11.3 लाख करोड़ रुपए हो गया है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात भी लगभग आठ गुना बढ़कर 0.38 लाख करोड़ रुपए से लगभग 3.3 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वैष्णव ने कहा कि भारत ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत तैयार उत्पादों के प्रोडक्शन से की थी, और अब ध्यान मॉड्यूल, सब-मॉड्यूल, घटकों और यहां तक कि मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया में उपयोग होने वाले कच्चे माल, औजारों और मशीनरी के विकास पर केंद्रित हो गया है। सरकार ने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन-संबंधित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई), इलेक्ट्रॉनिक घटकों और अर्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना शामिल हैं। मंत्री ने बताया कि आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना के तहत, तीन स्वीकृत आवेदकों ने महाराष्ट्र राज्य में विनिर्माण इकाइयां स्थापित की हैं, और ये सभी लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) हैं।

सेल ने अप्रैल-फरवरी में दर्ज की अब तक की सबसे अधिक स्टील बिक्री

नई दिल्ली। सरकारी स्टील कंपनी स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल से फरवरी अवधि के दौरान अब तक की सबसे अधिक स्टील बिक्री दर्ज की है। स्टील मंत्रालय ने बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी का प्रदर्शन लगातार मजबूत बना हुआ है।

मंत्रालय के अनुसार, महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सेल ने चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में कुल 18.24 मिलियन टन (एमटी) स्टील की बिक्री की, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 14 प्रतिशत अधिक है। यह कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

इसी अवधि में कंपनी का कैश कलेक्शन भी बढ़कर 1.11 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है, जो सालाना आधार पर लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। मंत्रालय के मुताबिक, रिटेल बिक्री में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। स्टॉकयार्ड बिक्री और घर-घर डिलीवरी सेवाओं में बढ़ोतरी कंपनी के ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाती है।

फरवरी 2026 के महीने में ही सेल ने कुल 1.58 मिलियन टन स्टील की बिक्री दर्ज की। साथ ही कंपनी ने अपने स्टॉक में भी कमी लाने में सफलता हासिल की है। जनवरी 2026 की तुलना में कंपनी ने अपने स्टॉक को 1.05 लाख टन तक कम किया और अपने कर्ज में 1,000 करोड़ रुपये की कटौती की है।

भारत का डिजिटल पेमेंट मॉडल बना विकासशील देशों के लिए मिसाल

नई दिल्ली भारत का डिजिटल पेमेंट मॉडल अब दुनिया के कई विकासशील देशों के लिए प्रेरणा बन गया है। एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार भारत ने आधुनिक इतिहास में सबसे महत्वाकांक्षी फिनटेक परिवर्तन को सफलतापूर्वक लागू करते हुए एक मजबूत और उन्नत डिजिटल भुगतान व्यवस्था विकसित की है।

अजरबैजान स्थित न्यूज डॉट एजेड की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने सरकारी नीतियों, तकनीकी नवाचार और तेजी से बढ़ती मोबाइल कनेक्टिविटी के सहारे एक प्रभावी डिजिटल भुगतान ढांचा तैयार किया है। यही कारण है कि आज भारत का डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम दुनिया के सबसे बड़े और उन्नत सिस्टमों में गिना जाता है।

रिपोर्ट के अनुसार भारत की डिजिटल पेमेंट क्रांति ने वैश्विक स्तर पर काफी ध्यान आकर्षित किया है। अर्थशास्त्री और तकनीकी विशेषज्ञ इसे अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक सफल मॉडल के रूप में देख रहे हैं और इसका अध्ययन कर रहे हैं।

रिपोर्ट में बताया गया है कि डिजिटल

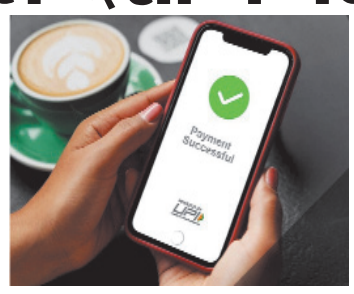

पहचान प्रणाली, मोबाइल इंटरनेट का तेजी से विस्तार, आधुनिक पेमेंट प्लेटफॉर्म और सरकार की सहायक नीतियों के संयोजन ने इस व्यवस्था को मजबूत बनाया है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लाखों लोगों को डिजिटल पहचान उपलब्ध कराने वाले सरकारी कार्यक्रमों ने इसकी नींव को मजबूत किया।

इसके साथ ही सस्ते स्मार्टफोन और तेजी से बढ़ती मोबाइल इंटरनेट सेवाओं ने डिजिटल भुगतान को आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वानी) योजना के तहत सार्वजनिक इंटरनेट सुविधाओं का भी तेजी से विस्तार हुआ है।

फरवरी 2026 तक इस पहल के अंतर्गत देशभर में 4,09,111 वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जा चुके हैं, जिन्हें 207 पीडीओ एग्रीगेटर और 113 ऐप प्रदाता सहयोग दे रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सस्ती और तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है।

इन सभी प्रयासों ने डिजिटल वित्तीय सेवाओं के व्यापक विस्तार के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल पहचान को बैंकिंग और मोबाइल सेवाओं से जोड़ने से उपयोगकर्ताओं की पहचान सुरक्षित तरीके से सत्यापित हो रही है और लेनदेन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2026 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से हर महीने लगभग 28.33 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन दर्ज किए गए। इस दौरान 21.7 अरब डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए, जिससे नकदी पर निर्भरता कम हुई है और वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी है।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में रियल एस्टेट निवेश का प्रमुख केंद्र बना भारतः रिपोर्ट

नई दिल्ली। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत रियल एस्टेट निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण और आकर्षक बाजार के रूप में लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। बुधवार को जारी कॉलियर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2025 में भारत ने इस क्षेत्र के नौ प्रमुख बाजारों में रियल एस्टेट निवेश के मामले में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की।

रिपोर्ट के अनुसार एशिया-प्रशांत के नौ प्रमुख बाजारों में 2025 के दौरान कुल रियल एस्टेट निवेश 162 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8 प्रतिशत अधिक है। वर्ष के दूसरे हिस्से में निवेश गतिविधियों में तेजी आई, क्योंकि खरीदार और विक्रेता कीमतों को लेकर एक-दूसरे के करीब आए। कॉलियर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि सिंगापुर और भारत में निवेश में सबसे अधिक बढ़ोतरी देखी गई। सिंगापुर में निवेश 35 प्रतिशत और भारत में 29 प्रतिशत बढ़ा, जो बेहतर बाजार परिस्थितियों और निवेश के बढ़ते अवसरों को दर्शाता है।

कॉलियर्स इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बादल याग्निक के अनुसार एशिया-प्रशांत के अधिकांश बाजारों में घरेलू पूंजी निवेश गतिविधियों को गति दे रही है, जबकि भारत में विदेशी निवेशकों की भागीदारी भी काफी मजबूत रही। कुल 8.5 अरब डॉलर के निवेश में लगभग 43 प्रतिशत हिस्सा विदेशी निवेशकों का रहा।

स्पेशल खबर बकाया लोन 10 लाख करोड़ से ज्यादा, ऋण सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक

देश में 7.72 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड सक्रिय

- देश में 7.72 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सक्रिय हैं।
- इन कार्डों पर कुल बकाया ऋण लगभग 10.2 लाख करोड़ रुपए है।
- केसीसी प्लेटफॉर्म से देश के 457 बैंक जुड़े हुए हैं।
- सरकार ने फसल ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है।
- डिजिटल पोर्टल और नई सुविधाओं से किसानों को ऋण प्राप्त करना आसान हुआ है।

नई दिल्ली, 11 मार्च (आईएएनएस)। देश में 7.72 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सक्रिय हैं और इनमें बकाया लोन 10.2 लाख करोड़ रुपए के करीब है। यह जानकारी बुधवार को आधिकारिक फैक्टशीट में दी गई।

सरकारी बयान में कहा गया कि केसीसी प्लेटफॉर्म से 457 बैंक जुड़े हुए हैं और इस पर 1,998.7 लाख से ज्यादा क्रेडिट एप्लीकेशन प्रोसेस की गई हैं, जिसमें से 631.5 लाख कमर्शियल बैंकों, 337.2 लाख रीजनल बैंकों और 1,030 लाख एप्लीकेशन कॉरपोरेटिव बैंकों द्वारा प्रोसेस की गई हैं।

ये आंकड़े केसीसी के कार्यान्वयन में व्यापक संस्थागत भागीदारी को दर्शाते हैं और कृषि ऋण प्रदान करने में सहकारी बैंकों की केंद्रीय भूमिका को उजागर करते हैं।

हालिया सुधारों, जिनमें ऋण सीमा में वृद्धि, संबद्ध क्षेत्रों तक विस्तारित कवरेज और किसान ऋण पोर्टल के माध्यम से डिजिटल एकीकरण शामिल हैं, ने केसीसी की पहुंच और पारदर्शिता में मजबूत सुधार किया है।

आंकड़ों पर आधारित निगरानी को सक्षम बनाकर, ऋण प्रक्रिया को तेज करके और पारदर्शी दावा निपटान सुनिश्चित करके, इन उपायों ने कृषि ऋण वितरण की परिचालन दक्षता को मजबूत किया है।

सरकार ने संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के तहत फसल ऋण सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है और मत्स्य पालन और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत, सीमांत और गैर-सीमांत किसानों के लिए उनकी भूमि जोत के आकार, निवेश क्षमता और आजीविका आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सावधि ऋण और समग्र ऋण सीमाएं अलग-अलग निर्धारित की गई हैं।

भूमि जोत के आकार और फसल पैटर्न जैसे कारकों के आधार पर 10,000 रुपए से 50,000 रुपए तक की लचीली सीमा स्वीकृत की जा सकती है। समग्र केसीसी सीमा पांच साल की अवधि के लिए निर्धारित की जाएगी।

किसानों को संस्थागत ऋण से जोड़ने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और उनकी पहुंच में सुधार लाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कई सुगम उपाय लागू किए गए हैं।